भारत संघ और अन्य

बनाम

विश्व प्रिया सिंह

(सिविल अपील सं. 8360/2010)

05 जुलाई, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, और उदय उमेश ललित, जे.]

सेना अधिनियम, 1950-एस.116 और 120-समरी कोर्ट मार्शल (एस. सी. एम.)-क्या अभियुक्त की वर्तमान इकाई के अलावा इकाई के कमांडिंग ऑफिसर (सी. ओ.) द्वारा बुलाया जा सकता है, गठित किया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है (यानी वह इकाई जिसमें अभियुक्त संलग्न है)-दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की रिट याचिकाओं को सी. ओ. की क्षमता के आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि एस. सी. एम. को अभियुक्त की वर्तमान इकाई के अलावा इकाई के सी. ओ. द्वारा बुलाया गया था, गठित किया गया था और पूरा किया गया था-राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के मामलों को योग्यता के आधार पर तय करने वाले मामलों को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाःयह आवश्यक नहीं है कि एस. सी. एम. को उस इकाई के सी. ओ. द्वारा बुलाया जा सकता है, गठित किया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है जिससे अभियुक्त संबंधित था-यह उस इकाई के सी. ओ. के लिए सक्षम और अनुज्ञेय है जिससे अभियुक्त को संलग्न किया गया था या मुकदमे के उद्देश्य से कुर्की पर भेजा गया था-यदि अपराध उस इकाई से जुड़ा है जिससे अभियुक्त जुड़ा हुआ है, तो संलग्न इकाई का सी. ओ. एस. सी. एम. बुलाने, गठन करने और पूरा करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वह मामले की निगरानी में है-मूल इकाई के सी. ओ. का ऐसे मामले में कोई लेना-देना नहीं है-दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाले मामलों

को योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए रिमांड पर लिया जाता है-अन्य मामले खारिज किए जाने योग्य हैं-सेना नियम, 1954-आर. आर.39, 133 और 146-रक्षा सेवा विनियम-नियम 9 और 381।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अपीलों को स्वीकार करते हुए और उन्हें उच्च न्यायालय में प्रेषित करते हुए, और अन्य अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1 सेना अधिनियम ने एक एकल व्यक्ति, अर्थात् कमांडिंग ऑफिसर (सी. ओ.) को कठोर शक्ति दी है, जिसे अकेले न्यायालय का गठन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शक्ति सेना अधिनियम, 1950 की खंड 120 की उप-खंड (4) और (5) के संदर्भ में प्रतिबंधों के साथ आती है।हालाँकि, इस तरह के प्रतिबंधों के बावजूद शक्ति काफी कठोर है। इस तरह की शक्ति प्रदान आदेशने का कारण स्पष्ट है कि सैनिकों और इकाइयों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए,सी. ओ. के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि यह वह अनुशासन है जो काफी हद तक इकाई को बांधता है और इसे एक सह-चिपकने वाला बल बनाता है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करने में आत्यन्तिक रूप से सही था कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए और जब यह बिल्कुल जरूरी हो तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। उस ओर से संतुष्टि या तो लिखित रूप में व्यक्त की जानी चाहिए या रिकॉर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए, विशेष रूप से जब सशस्त्र बल न्यायालय अधिनियम, 2007 के लागू होने के साथ किसी न्यायालय द्वारा मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। [पैरा 19,20] [495-जी-एच; 496-ए-सी]

2 यह नहीं कहा जा सकता है कि एस. सी. एम. द्वारा 1950 के अधिनियम

की खंड 34,37 और 69 के तहत केवल अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1950 के अधिनियम की खंड 120 (2) के प्रावधान में वरिष्ठ प्राधिकारी के संदर्भ की आवश्यकता होती है, जिसे नियमों के सेना नियम 22 (3) के प्रावधान में फिर से प्रतिध्वनित किया गया है, एक लाभप्रद प्रावधान है और एक सी. ओ. को प्रदान की गई कठोर शक्ति के प्रयोग पर रोक है और इसका सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता के गैर-पालन के लिए एक मामला रिकॉर्ड पर बनाया जाना चाहिए और किसी भी विचलन या वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-पालन को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के तहत अपराध विशेष श्रेणियां या प्रकार के अपराध हैं जहां एक डी. सी. एम. या एस. जी. सी. एम. को बुलाने के लिए सशक्त अधिकारी का संदर्भ अनिवार्य माना जाता है जब तक कि तत्काल कार्रवाई के लिए गंभीर कारण न हों।इसी तरह, न्यायालय धारण करने वाले अधिकारी के खिलाफ अपराध, जहां वह अधिकारी संभवतः "अपने मामले में न्यायाधीश हो सकता है", को भी उसी स्तर पर रखा जाता है और उप-खंड (2) के तहत इसी तरह का संदर्भ दिया जाना चाहिए। इस तरह के संदर्भ की मांग करने में शक्ति का प्रयोग और इसके संबंध में परिणामी विचार इन अपराधों के संबंध में जुड़ी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।[पैरा 22,23] [497-सी-एफ]

3.1 इस सवाल के संबंध में कि कौन सी. ओ. एस. सी. एम. को बुलाने, गठित करने और पूरा करने के लिए सक्षम है। क्या यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे अभियुक्त संबंधित था या उस इकाई का सी. ओ. है जिससे वह जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ था। इस संबंध में संभवतः तीन प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं:(क) एक अभियुक्त जो अपनी नियमित इकाई का हिस्सा रहते हुए अपराध का गठन करने वाला कार्य करता है, उस पर एस. सी. एम. द्वारा उसके अपने सी. ओ. यानी इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा

चलाया जाता है। (ख) एक अभियुक्त एक अलग इकाई से संलग्नक होने के दौरान एक अपराध का गठन करने वाला कार्य करता है और इसलिए उस पर ऐसी इकाई के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जिस पर उसे संलग्नक पर भेजा गया था। ऐसे मामलों में अपराध तब किया जाएगा जब आरोपी कुर्की पर था। (ग) अपनी नियमित इकाई का हिस्सा रहते हुए अपराध का गठन करने वाला कार्य करने वाले अभियुक्त को बाद में एक अलग इकाई में कुर्की पर भेजा जाता है और फिर ऐसी इकाई के सी. ओ. यानी इकाई द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जहां अपराध के बाद उसे कुर्की पर भेजा गया था।[पैरा 24] [497-जी-एच; 498-ए-बी]

3.2 एस. सी. एम. द्वारा अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से उस इकाई के सी. ओ. पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे अभियुक्त संबंधित है। इसलिए ऊपर वर्णित अपराधों की उपरोक्त तीन श्रेणियों में से पहले पर निश्चित रूप से उस इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिससे वह संबंधित है। यदि अपराध का गठन करने वाला कार्य उस इकाई से जुड़ा हुआ है जब ऐसा कार्य किया गया था, तो दूसरी श्रेणी में आने वाले मामलों के संबंध में, अपराध का तार्किक रूप से उस इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिससे आरोपी जुड़ा हुआ था। अभियुक्त इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि केवल उसकी मूल इकाई के सी. ओ. को एस. सी. एम. द्वारा उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल इकाई के साथ उसके पूर्व संबंध को इस हद तक शासी कारक के रूप में लिया जाना चाहिए कि इकाई का सामान्य संबंध और विचाराधीन अपराध विस्थापित हो जाए। यदि खंड 120 (2) की आवश्यकताओं का अन्यथा अनुपालन और संतुष्टि की जाती है, तो ऐसी संलग्न इकाई का सी. ओ. एस.

सी. एम. बुलाने, गठित करने और पूरा करने में सक्षम है। यह उनकी इकाई में है कि विचाराधीन अपराध किया गया था और उस अर्थ में वह मामले की निगरानी में होगा।मूल इकाई के सी. ओ. का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं होगा।[पैरा 25] [498-सी-एफ]

3.3 तीसरी श्रेणी में दो उप-श्रेणियाँ हो सकती हैं।पहले में, अपराध के बारे में ही पता चल सकता है, हालांकि अपराध मूल इकाई में किया गया था, जब आरोपी को कुर्की पर भेजा गया था। दूसरा, एक अभियुक्त को केवल उस दूसरी इकाई के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाए जाने के लिए दूसरी इकाई में कुर्की पर भेजा जा सकता है। पूर्ववर्ती इकाई के साथ संबंधित होने और उस इकाई के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण एक अपराध का गठन करने वाले अधिनियम का आयोग, जहां उसे बाद में कुर्की पर भेजा जाता है, आम तौर पर विचाराधीन इकाइयों में से पूर्व उपयुक्त होगा। लेकिन, जब अपराध स्वयं पूर्व इकाई के सी. ओ. के खिलाफ किया गया हो या सी. ओ. मुद्दे के मामलों पर या अनुशासन के उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है, तो अभियुक्त को विचाराधीन इकाई से बाहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है।[पैरा 26,27] [498-जी-एच; 499-ए-बी]

3.4 यदि प्रक्रिया में निष्पक्षता की अवधारणा की मांग की जाती है, जैसा कि नियमों के नियम 39 के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जिस इकाई से कोई आरोपी संबंधित है, उसके सी. ओ. को जी. सी. एम. या डी. सी. एम. पर सेवा करने का अधिकार नहीं है, तो अपराध के संबंध में ऐसे सी. ओ. की स्थिति और भूमिका की परवाह किए बिना, उस इकाई के सी. ओ. पर एस. सी. एम. बुलाने का हकदार एकमात्र प्राधिकरण होने का आग्रह करना पूरी तरह से विरोधाभास होगा। धारा 116 और 120 इस तरह के किसी

भी निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके विपरीत किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में में, विनियमन 9 निश्चित रूप से मार्गदर्शक कारक हो सकता है। खंड 116 में "कमांडिंग ऑफिसर" अभिव्यक्ति किसी भी स्पष्टीकरण से योग्य नहीं है कि वह उस इकाई का सी. ओ. होना चाहिए जिससे आरोपी संबंधित है। रक्षा सेवा विनियम (डी. एस. आर.) का विनियम 9, अपनी चौड़ाई और विस्तार के साथ इस तरह की व्याख्या प्रदान करता है और निष्पक्षता और निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। [पैरा 29] [499-जी-एच; 500-ए-बी]

3.5 उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सभी परिस्थितियों में, विनियमन 381 द्वारा निपटाए गए मामलों के अलावा, यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे आरोपी संबंधित है, अकेले एस. सी. एम. बुलाने, गठित करने और पूरा करने के लिए सक्षम है, गलत है। [पैरा 30] [500-डी]

3.6 जी. सी. एम. या डी. सी. एम. के संदर्भ में सेना नियमों के नियम 39 में "जिस पद से अभियुक्त संबंधित है" का उल्लेख मिलता है, लेकिन एस. सी. एम. के संबंध में नहीं। नियमों के नियम 133 के तहत एक एस. सी. एम. की कार्यवाही को घोषणा के तुरंत बाद उस कमान के उप न्यायाधीश महाधिवक्ता द्वारा से अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमें मुकदमा आयोजित किया जाता है। दूसरी ओर, नियमों के नियम 146 के तहत एक एस. सी. एम. की कार्यवाही को उस दल या विभाग के रिकॉर्ड के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए जिससे आरोपी संबंधित थे। इस प्रकार यह संभव और सुविचारित है कि एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा उस इकाई के अलावा किसी अन्य इकाई में आयोजित किया जा सकता है जिससे आरोपी संबंधित है।नियम 39 और 146 आगे खुलासा करते हैं कि जहां भी अधिनियम उस इकाई या

विभाग को निर्दिष्ट करना चाहता था "जिससे आरोपी संबंधित था" उसने इसे बहुत स्पष्टता के साथ किया है।सी. ओ. के संबंध में ऐसी कोई योग्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है जिसे एस. सी. एम. का आयोजन, गठन और पूरा करना है। [पैरा 31] [500-ई-जी];

3.7 यह जरूरी नहीं है कि एस. सी. एम. को उस इकाई के सी. ओ. द्वारा बुलाया जाए, गठित किया जाए और पूरा किया जाए जिसमें आरोपी शामिल थे। जिस इकाई से अभियुक्त को संबद्ध किया गया था या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए कुर्की पर भेजा गया था, उस इकाई के सी. ओ. के लिए यह सक्षम और अनुज्ञेय है कि वह ऐसे अभियुक्त पर कानून द्वारा ज्ञात तरीके से, यानी अधिनियम की धारा 116 और 120 और अन्य सांविधिक प्रावधानों की सीमाओं के भीतर सख्ती से एस. सी. एम. बुलाकर, गठित करके और पूरा करके मुकदमा चलाए। एस. सी. एम. एक अपवाद है और यह अनिवार्य है कि कार्रवाई की तत्कालता के लिए एक मामला बनाया जाना चाहिए। एस. सी. एम. बुलाने के कारणों का अच्छी तरह से स्पष्ट कारणों से पालन किया जाना चाहिए या रिकॉर्ड को ही इस तरह के उपाय को उचित ठहराना चाहिए।[पैरा 33] [501-बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयःसिविल याचिका सं 8360/ 2010

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल रिट याचिका (सी) संख्या 2511/1992 के निर्णय और आदेश दिनांक 25.01.2008 से।

के साथ

सी. ए. संख्या 8838 और 8830-8835/2010

सी. ए. संख्या 2547,2548,2549,2550 और 10104/2011

सी. ए. सं. 6679/2015

सी. ए. डी. सं. 13803 और 18038/2015

अरुण मोहन (एसी), सुश्री ज्योति सिंह (एसी), सुश्री रेखा पल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजभूषण, आर. बालासुब्रमण्यम, संतोष कुमार, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, अजय शर्मा, प्रभास बजाज, प्रणव कुमार, बी. वी. बलराम दास, श्रीमती अनिल कटियार, एम. जी. कपूर, देवेंद्र कुमार सिंह, सी. पी. सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, संतोष मिश्रा, सूर्यकांत, बिनय के. दास, रंजीत शर्मा, सुश्री प्रियंका दास, रविशंकर रवि, आर. डी. उपाध्याय, सुधांशु एस. पाडे, श्रीधर पोटराजू, गैचांगपोउ गंगनेई, अभिषेक आर. शुक्ला, मुकुंद राव , अर्जुन सिंह, मेजर के. रमेश, वी. सुशांत गुप्ता, डॉ. कैलाश चंद,उपस्थित दलों के लिए।

उत्तरदाता-व्यक्ति

न्यायालय का निर्णय उदय उमेश ललित, जे. द्वारा दिया गया था।

1. सिविल अपील सं.8360/2010 और 8830-8835/2010, भारत संघ के कहने पर, रिट याचिका (सिविल) सं.2511/1992, 3519/1998, 6185/2002, 2433/2003, 17622/2004, 18185/2004 और 20233/2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.01.2008 के सामान्य निर्णय और आदेश की शुद्धता को चुनौती देती है। की सिविल अपील सं.8838/2010 रिट याचिका सं.4341/1999 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 02.05.2008 के फैसले पर हमला करने का प्रयास करती है, जो दिनांक 25.01.2008 के पहले के फैसले पर निर्भर करता है।

2. सुविधा के लिए हम देथी उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.01.2008 के फैसले के अनुच्छेद सं.2 से 7 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसके समक्ष प्रत्येक याचिका में तथ्यात्मक मैट्रिक्स को निकालता है। उक्त अनुच्छेद सं. 2 से 7 के तहत

हैं:-

"2. सी. डब्ल्यू. पी. 2511/1992 में याचिकाकर्ता, एक्स. एल. एन. के. विश्व प्रिया सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 19 वीं बटालियन महार रेजिमेंट सीओ के खिलाफ याचिकाकर्ता के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत की थी। रिट याचिका में यह कहा गया है कि शुरू में ब्रिगेड कमांडर ने याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच के लिए सीओ, 17 वें कुमाऊं को नामित किया था। 19 वीं महार के सी. ओ. ने हेरफेर द्वारा से अपने करीबी दोस्त, 18 वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट के सी. ओ. को इन शिकायतों की जांच के लिए विस्तृत जानकारी दी। याचिकाकर्ता को 18 वीं पंजाब रेजिमेंट में जाने का आदेश दिया गया। आखिरकार, सी. ओ., 18 वीं पंजाब रेजिमेंट ने एस. सी. एम. द्वारा याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया और उसे सिविल जेल में छह महीने की कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई। तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता 19 वीं महार का था, लेकिन 18 वीं पंजाब रेजिमेंट के सी. ओ. द्वारा आयोजित एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया गया था, इसलिए मुकदमे को कोरम-न्यायिक माना गया।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने अपने 'सी. ओ. के खिलाफ 26.3.1990 पर शिकायत की थी; ब्रिगेड कमांडर द्वारा 30.5.1990 पर उनका साक्षात्कार लिया गया था; उन्हें सी. ओ., 18 वीं पंजाब रेजिमेंट के समक्ष 15.7.1990 पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था; उन पर सेना अधिनियम की खंड 41 (2) के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए वैध आदेश की अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्हें, जब दिनांक 16.7.1990 एक

पत्र को प्रतिग्रहण करना करने के लिए कहा गया था, जिसमें यूनिट में जांच के लिए सी. ओ. के कार्यालय में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मौखिक आदेशों की अवज्ञा की।

2. एक्स. एनके प्रेम सिंह ने सी. डब्ल्यू. पी. 3519/1998 दायर कर दलील दी है कि वह 15 आई. एन. एफ. डी. आई. वी. ओ. आर. डी. इकाई से संबंधित हैं जो दावा स्वीकार किया जाता है। 17.4.1998 पर उन पर सेना अधिनियम की खंड 40 (ए) के तहत अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने 20.10.1997 पर अमृतसर में कंपनी हैव मेजर क्लर्क के सिर और पैरों पर लोहे के उपकरण से वार किया था। याचिकाकर्ता को (ए) रैंक तक कम करने, (बी) सेवा से बर्खास्त करने और (सी) सिविल जेल में छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. सी.ओ., 194 फील्ड रेजिमेंट ने एस. सी. एम. का आयोजन किया जो 21.4.1998 पर समाप्त हुआ। प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए 194 फील्ड रेजिमेंट के साथ दिनांकित 21.10.1997 पत्र के माध्यम से संलग्न किया गया था।जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 में यह कहा गया है कि जिस घटना के लिए याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था, वह 20.10.1997 की शाम को हुई थी। उन्हें उनकी इकाई के सी. ओ. द्वारा हिरासत में ले लिया गया और चूंकि उनकी इकाई में कोई क्वार्टर गार्ड नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता को सुरक्षित हिरासत के

लिए 194 फील्ड रेजिमेंट की ओर क्वार्टर गार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। यह आगे अनुरोध किया गया है कि 24.10.1997 दिनांकित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए इकाई के साथ संलग्न किया गया था, ताकि उसके खिलाफ जांच को अंतिम रूप देने तक संलग्न रहे।दूसरे शब्दों में, घटना जो एस. सी. एम. का विषय है और एस. सी. एम. के आयोजन के बीच छह महीने बीत चुके थे।

4. सी. डब्ल्यू. पी. 6185/2002 पूर्व द्वारा दाखिल किया गया है। एन. के. द्वारका प्रसाद ने कहा कि वह 24 वीं राजपूत रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2000 में सहायक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से 61 वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड से जोड़ा गया था।सेना अधिनियम की खंड 69 के तहत दिनांक 29.10.2001 आरोप-पत्र द्वारा उन पर 25.10.2001 पर एक नागरिक अपराध करने का आरोप लगाया गया था, अर्थात एक महिला की शील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करना और उसी तारीख को 65 वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने आदेश दिया कि उन पर एक एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जाए। याचिकाकर्ता पर एस. सी. एम. द्वारा 3.11.2001 और 5.11.2001 के बीच मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया/सजा सुनाई गई (1) रैंक तक कम किया जाना (2) सेवा से बर्खास्त किया जाना, (3) एक साल के लिए दीवानी जेल में कारावास भुगतना।

5. सी. डब्ल्यू. पी. 2433/2003 पूर्व द्वारा दाखिल किया गया है। हवलदार धरमबीर कांकेर जिन्हें सैन्य पुलिस के कोर में हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था।सोलह वर्षों के बाद उन्हें असम के तेज़पुर में चौथी कोर प्रोवोस्ट यूनिट में तैनात किया गया था। 9.6.2000 दिनांकित आरोप-पत्र द्वारा याचिकाकर्ता पर सेना अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था। 22.6.2000 पर एससीएम ने याचिकाकर्ता (ए) को रैंक तक कम करने और (बी) सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई।

6. सी. डब्ल्यू. पी. 20233/2005 सिपाही यू. एस. मिश्रा द्वारा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें मार्च, 1987 में भारतीय सेना में नामांकित किया गया था और 18.3.1999 पर उन्हें 38 डिफेंस मेडिकल स्टोर डिपो में तैनात किया गया था। 27.3.2002 दिनांकित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए 38 ए. एम. एस. डी. ब्लॉकों में संलग्न किया गया था। याचिकाकर्ता पर सेना के 15 कर्मियों के साथ सी. ओ. 118 फील्ड रेजिमेंट द्वारा एस. सी. एम. द्वारा 20.12.2004 और 4.1.2005 के बीच मुकदमा चलाया गया, जहां याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए संलग्न किया गया था।सेना अधिनियम की खंड 52 (एफ) के तहत पहला आरोप यह था कि 4.8.1999 से 6.6.2001 के बीच याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी करने के इरादे से इश्यू वाउचर में कई प्रविष्टियों को अनुचित तरीके से बदल दिया।याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया और उसे 4.1.2005 पर रैंक तक कम करने की सजा

सुनाई गई।तर्क यह है कि 118 फील्ड रेजिमेंट के सी. ओ. एस. सी. एम. द्वारा याचिकाकर्ता पर मुकदमा नहीं चला सके क्योंकि वह केवल 'इकाई से जुड़े' थे।एस. सी. एम. के आयोजन में देरी पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा।

7. सेप/क्लर्क एस. के. नायर द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. 17622/2004 और सेप/क्लर्क बलविंदर सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. 18185/2004 में तथ्य समान हैं।सितंबर 1998 में मार्च 1995 में पठानकोट में आयोजित एक भर्ती रैली के दौरान अनियमित नामांकन की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि उन्हें 14 वीं सिख रेजिमेंट में तैनात किया गया था, इसलिए केवल उस इकाई का सीओ ही एससीएम द्वारा उन पर मुकदमा चलाने में सक्षम था। तदनुसार, टी. बी. ए. एस. सी. केंद्र, गया के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. कानूनी रूप से अक्षम और गैर-स्थायी था।एस. सी. एम. के आयोजन में देरी पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा।"

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं ने सारांश न्यायालय मार्शल से संबंधित कानून के दो सामान्य प्रश्न उठाए (इसके बाद एस. सी. एम. के रूप में संदर्भित):-

(क) क्या एक एस. सी. एम. को उस इकाई के कमांडिंग ऑफिसर (संक्षेप में "सी. ओ".) द्वारा बुलाया जा सकता है, गठित किया जा सकता है और ए. को पूरा किया जा सकता है जिससे आरोपी संबंधित नहीं थे और

(ख) वे परिस्थितियाँ जिनमें सेना अधिनियम 1950 की खंड 108 (जिसे इसके

बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में परिकल्पित सामान्य न्यायालय मार्शल (संक्षेप में "जी. सी. एम".), जिला न्यायालय मार्शल (संक्षेप में "डी. सी. एम".) या सारांश सामान्य न्यायालय मार्शल बी (संक्षेप में "एस. जी. सी. एम".) के बजाय एस. सी. एम. को बुलाया जा सकता है।

इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 20,22,23 और 24 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> “20. एक एस. सी. एम. को वैध रूप से बुलाया जा सकता है जहां गंभीर सी. सी. हो और तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने वाला कारण हो, जिसे पराजित किया जाएगा यदि जिला कोर्ट मार्शल या सारांश जनरल कोर्ट मार्शल का संदर्भ दिया जाता है, दूसरे शब्दों में, एस. सी. एम. का आयोजन अपवाद है न कि नियम।कई संभावित अपराधों में से केवल धारा 34,37 और 69 में परिकल्पित अपराधों पर ही एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, जो एस. सी. एम. के असाधारण और असाधारण चरित्र को और मजबूत करता है। हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि केवल इसलिए एस. सी. एम. बुलाना उचित नहीं है क्योंकि इन तीन धाराओं में निहित गणना में बल के एक सिपाही पर जिस अपराध (अपराधों) का आरोप लगाया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। एस. सी. एम. बुलाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनिवार्य पाया जाना चाहिए कि तत्काल कार्रवाई स्पष्ट रूप से आवश्यक है।इसलिए, यह आवश्यक है कि एस. सी. एम. को बुलाने के आदेश में इस कारक को, अर्थात तुरंत एक परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाए और लिखित रूप में तर्क दिया जाए। ऐसा करने में विफलता एस. सी. एम. को ही रद्द करने का अच्छा कारण बनेगी।नियमित रूप से, और निश्चित रूप से बहुत अधिक बार, एस. सी. एम.

द्वारा पारित सजा विनियमन 448 (सी) (उपरोक्त) की भावना का उल्लंघन करती है जिससे सिपाहियों को कानून की सामान्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान किए बिना उनकी आजीविका छीन ली जाती है।

21.....

22. हम सबसे पहले जी को स्पष्ट करते हुए इस कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे कि यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे आरोपी संबंधित है जिसे एस. सी. एम. बुलाने का अधिकार है। यह कोई खाली औपचारिकता या व्यर्थ समयबद्धता नहीं है। सीओ और उनके शासन के बीच एक स्थायी और गर्भ संबंध है। रैंकों ने हमेशा अपने सीओ को पिता के रूप में देखा है जो उनके कल्याण के साथ-साथ उनके अनुशासन के साथ भी चिंतित होंगे। सेना अधिनियम, नियमों और विनियमों के समग्र अध्ययन पर यह एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है।;

23. ऊपर दिए गए हमारे विश्लेषण के अनुसार, इस नियम का अपवाद रेगिस्तानियों के मामले तक ही सीमित है और वह भी जहां उस इकाई का सी. ओ., जिससे वे संबंधित हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं है।दूसरा, एक एस. सी. एम. अपवाद होना चाहिए न कि नियम।इसे केवल तभी बुलाया जा सकता है जब आवश्यकताएं तत्काल और त्वरित निर्णय की मांग करती हैं जिसके बिना स्थिति व्यापक प्रभावों के साथ निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जाहिर है, जहां अपचारी या अनुशासनहीन कार्रवाई एक व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है या नागरिक कानून के आयाम हैं, एक एससीएम का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।इस प्रकार देरी एक एस. सी. एम. के लिए घातक हो जाएगी। तीसरा, एस. सी. एम. बुलाने के निर्णय से पहले एक तर्कपूर्ण आदेश

होना चाहिए जो स्वयं न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। हम निश्चित हैं कि एक बार इस औपचारिकता का पालन हो जाने के बाद, निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त अधिकारों की अपरिहार्य अवहेलना स्वचालित रूप से उन दुर्लभ मामलों तक ही सीमित हो जाएगी जहां एक अनुशासित सैन्य बल को बनाए रखने के हित भारत के नागरिक के छोटे नागरिक अधिकारों के संरक्षण से कहीं अधिक हैं।

24. याचिकाओं में वर्णित तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संदर्भ में कानून के इस विश्लेषण में, हमने विवादित एस. सी. एम. के फैसले को इस संक्षिप्त आधार पर दरकिनार कर दिया कि यह उस इकाई के सी. ओ. द्वारा आयोजित, गठित और पूरा नहीं किया गया था, जिसके लिए याचिकाकर्ता था। हम इस तथ्य को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं कि विश्व प्रिया सिंह की याचिका में स्थिति जटिल है, क्योंकि उस इकाई के सी. ओ. के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जिससे याचिकाकर्ता संबंधित है। यदि सी. ओ. स्वयं बैठक बुलाता है एस. सी. एम. यह उनके अपने मामले में एक न्यायाधीश होने के समान होगा। न्यायालय के पटल पर अक्सर यह कहा जाता रहा है कि कठिन मामलों को खराब कानून नहीं बनाया जाना चाहिए।इसलिए, समाधान किसी भी अन्य कोर्ट मार्शल का गठन करने में निहित हो सकता है, आपातकालीन आधार पर यदि परिस्थितियाँ इस तरह से निर्धारित करती हैं। याचिकाकर्ताओं में से किसी पर भी सशस्त्र बलों में सबसे निंदनीय अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, जो कि रेगिस्तान का है।भले ही इस तरह से आरोप लगाया गया हो, यह उस इकाई के सी. ओ. द्वारा एक एस. सी. एम. के आयोजन के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए था, जिसमें याचिकाकर्ता संलग्न था, कि जिस इकाई से आरोपी संबंधित था, उसका सी.

ओ. ऊंचाई वाले क्षेत्र में या विदेशों में या विद्रोह विरोधी अभियानों या सक्रिय शत्रुता या अंडमान में कार्यरत था। और निकोबार द्वीप समूह।हम स्पष्ट करते हैं कि चूंकि मुकदमा नहीं चल रहा है, इसलिए प्रतिवादी कानून के अनुसार प्रतिवादीओं के खिलाफ नए सिरे से बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

4. अपने फैसले के दौरान, दिल्ली बी के उच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 116 और 120 के साथ-साथ खंड 116 के नीचे ध्यान दें 5 और खंड 120 के नीचे ध्यान दें 5 के साथ-साथ रक्षा सेवा विनियमों के पैराग्राफ 381 (जिसे इसके बाद "डी. एस. आर". के रूप में संदर्भित किया गया है) पर विचार किया। उच्च न्यायालय के अनुसार, डी. एस. आर. के पैराग्राफ 381 में बताए गए पलायन करने वालों के मुकदमे से संबंधित मामलों में, एक विशिष्ट अपवाद बनाया गया था, जिससे उस इकाई के सी. ओ. को सक्षम बनाया गया था, जिसमें आरोपी एक एस. सी. एम. बुलाने, गठित करने और पूरा करने से संबंधित था। इस तरह के अपवाद को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अनुसार, यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे आरोपी संबंधित है, जिसे अकेले एस. सी. एम. बुलाने, गठन करने और पूरा करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि एस. सी. एम. बुलाने के लिए यह अनिवार्य था कि तत्काल कार्रवाई स्पष्ट रूप से आवश्यक थी।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न अपीलों के साथ, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कहने पर सिविल अपील 2547-2550/2011 जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 31.08.2006 के सामान्य निर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हुए, उनकी रिट याचिकाओं को खारिज करने से उत्पन्न उनकी अपीलों को खारिज करते हुए, हमारे सामने रखी गई थी। यद्यपि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उस इकाई के सी. ओ. की क्षमता के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया गया था, जिसमें अभियुक्त एस. सी. एम. बुलाने, गठित करने और पूरा करने से संबंधित था, लेकिन राजस्थान

उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों में उन परिस्थितियों के बारे में प्रश्न उठाया गया था जिनमें जी. सी. एम. या डी. सी. एम. या एस. जी. सी. एम. के बजाय एस. सी. एम. बुलाया जा सकता था। किसी भी मामले में, हम पहले के प्रश्न के संबंध में भी इन अपीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

6. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर विचार किया गया था, उनके तथ्यात्मक पहलू, जैसा कि वर्तमान अपीलार्थियों से संबंधित अपने फैसले में पाया गया था, निम्नानुसार थेः-

> "रिट याचिका सं.2490/1987 17/18 मई, 1987 की रात के 0030 घंटे, जब उन्हें संतरी ड्यूटी पर होना था, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। सेना अधिनियम की खंड 63 के तहत अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल कार्य आदेशने के लिए संक्षिप्त कोर्ट मार्शल। कोर्ट-मार्शल के अधीन होने से पहले, एक स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में साक्ष्य का सारांश दर्ज किया जाता था, उसे आरोप और गवाह के नाम बताए जाते थे। याचिकाकर्ता ने आरोप-पत्र की प्रति और साक्ष्य के सारांश को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया। संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के दौरान, परिस्थितियों में, दो गवाहों की उपस्थिति में उन्हें आरोप पढ़ा दिया गया था। कार्यवाही पूरी होने पर, उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में घटाकर छह महीने कर दिया गया और 14.6.1987 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।प्रतिवादी के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना तब हुई थी जब इकाई डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तैनात थी।'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के दौरान सीमा से।पड़ोस में एक घटना हुई थी जिसमें सेना के कुछ कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और इन परिस्थितियों में निर्देश जारी किए गए थे आस-पास के गाँवों को

'सीमा से बाहर' क्षेत्र घोषित करना। निर्देशों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता उक्त क्षेत्र में गया, उसे आधी रात को उस दिशा से भागते देखा गया। उन्होंने दलील दी कि वह पासवर्ड जानने के लिए उस तरफ गए थे। इसका जवाब इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले दो लाल स्याही प्रविष्टियां की गई थीं।(i) सेना की खंड 39 (ए) के तहत छुट्टी बिना अनुपस्थिति के लिएःअधिनियम; और (ii) सेना अधिनियम की खंड 63 के तहत अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन (शराब का सेवन) के लिए प्रतिकूल कार्य आदेशने के लिए। प्रासंगिक समय में, उन्होंने चार साल और दस महीने की सेवा की, जिसमें एक वर्ष भर्ती के रूप में भी शामिल था।

रिट याचिका सं.5506/1994 में, याचिकाकर्ता दिलीप सिंह को 1986 में सिपाही (नर्सिंग सहायक) के रूप में सेना में नामांकित किया गया था। उन पर 1600 से 2200 घंटे तक 1.8.1993 पर यूनिट लाइन से छुट्टी बिना अनुपस्थिति रहने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् सब/NA एन एच.एन.गौतम और एच. वी./एन. ए. शवाले बाबसाहब श्रीमुरी पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिन पर उन्होंने कथित तौर पर उनके चेहरे और छाती पर हाथों से हमला किया था। साक्ष्य का सारांश दर्ज किया गया था। उन्होंने जिरह करने से इनकार कर दिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्हें आरोप पत्र की प्रति, साक्ष्य का सारांश प्रदान किया गया था। संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के चरण में, उन्हें फिर से अपने दोष स्वीकार करने के आरोपों और परिणामों से अवगत कराया गया।याचिकाकर्ता ने फिर से अपना अपराध स्वीकार कर लिया।उन्हें तीन महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई और 7.8.1993 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बिना किसी सफलता के अपील को प्राथमिकता दी। रिट याचिका सं.5689/1994 में,

याचिकाकर्ता भगवान सहाय को 8.1979 पर सेना में सिपाही के रूप में नामांकित किया गया था। जबकि उन्हें 5011 ए. एस. सी. बी. एन. (एम. टी.) के साथ संलग्न डीईटी.515 ए. एस. सी. बी. एन. के साथ तैनात किया गया था, उन्हें 16.3.1992 से 26.4.1992 तक 42 दिनों की वार्षिक छुट्टी मंजूर की गई थी। वह 27.4.1992 पर रिपोर्ट करने में विफल रहा। उन्हें छुट्टी बढ़ाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में सूचित किया गया था। अंततः उन्होंने 302 दिनों तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने के बाद 2.2,1993 पर शामिल होना स्वीकार कर लिया। आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और साक्ष्य का सारांश दर्ज किया गया, जिसके दौरान उन्हें गवाह से जिरह करने और बचाव में अपनी खुद की जांच करने का अवसर दिया गया। उन्होंने गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव में कोई बयान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।इसके बाद सारांश कोर्ट मार्शल आयोजित किया गया। आरोप की व्याख्या की गई और कागजात की आपूर्ति की गई, और उसे 'आरोपी का दोस्त' प्रदान किया गया और अपराध स्वीकार करने के परिणामों के बारे में सूचित किया गया। दिए गए कागजातों को देखने के बाद, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जो दर्ज किया गया था। उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया और सेना अधिनियम की खंड 38 (1) के तहत आरोप का दोषी ठहराया गया और 8.4.1993 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।उन्होंने अपील को प्राथमिकता दी जिसे 26.7.1994 पर खारिज कर दिया गया था।

रिट याचिका सं.6134/1994 में, याचिकाकर्ता छतर सिंह को 28.9.1976 पर सेना में नामांकित किया गया था। वह आदतन अनुपस्थित साबित हुए।वह 1.1.1982 से 2.11.1982 तक 12 दिनों तक बिना छुट्टी के

ड्यूटी से अनुपस्थिति रहे, जिसके लिए उन्हें 21 दिन की सजा दी गई थी 6.12.1982 पर सैन्य हिरासत में कठोर कारावास उन्होंने 8.10.1991 से 13.10.1991 तक 05 दिनों के लिए पर्याप्त कारण के बिना छुट्टी ली, जिसके लिए उन्हें समरी कोर्ट मार्शल के बाद रैंक में कमी का जुर्माना दिया गया था। सजा को तकनीकी आधार पर दरकिनार कर दिया गया था और प्राधिकरण नए सिरे से कार्यवाही करने की सलाह दी गई थी। ताजा कार्यवाही के बाद, रैंक में कमी का वही दंड 24.10.1992 पर दिया गया था। वह फिर से 28.10.1992 से 16 दिनों तक बिना छुट्टी के अनुपस्थिति रहे। सजा के उपरोक्त आदेश के चार दिनों के भीतर। इससे पहले भी, उन्होंने 13.7.1992 से 14.7.1992 तक 02 दिनों के लिए छुट्टी ली थी, और 19.8.1992 से 01.09.1992 तक बिना छुट्टी के अनुपस्थिति रहे, जिसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल के अधीन किया गया था।संक्षिप्त अदालती वैवाहिक कार्यवाही के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।उन्हें आरोप की प्रकृति और अपराध स्वीकार करने के परिणामों और अपराध स्वीकार करने के मामले में प्रक्रिया में अंतर के बारे में बताया गया था।उन्हें खंड 39 (ए) और (बी) के तहत आरोप का दोषी पाया गया और 5.1.1993 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।उन्होंने अपील को प्राथमिकता दी जिसे 28.6.1994 पर खारिज कर दिया गया था।"

7. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों को उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया था। यह देखा गया कि विचाराधीन नियमों में न केवल शामिल थे। पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए लेकिन कार्यवाही में उचित स्तर की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई। यह देखा गयाः-

"यदि नियम 22 के तहत किसी अभियुक्त पर संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल

द्वारा मुकदमा चलाने का कमांडिंग अधिकारी का निर्णय आरोप की प्रकृति, आरोप के बिंदु पर सुनवाई के चरण में एकत्र किए गए साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो यह स्पष्ट है कि संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और यदि ऐसा है, तो वकील का उप-मिशन कि संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमे का विकल्प अपराधी की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि अपराध की प्रकृति पर खारिज किया जाना चाहिए।यह याचिकाकर्ता के मामले का जोर था। हम उसमें कोई पदार्थ नहीं पाते हैं।"

8. सिविल अपील सीएडी सं.13803/2015 और 18038, भारत संघ के कहने पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा टीए सं 6 और 8/2011 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 13.12.2015 को चुनौती देना चाहते हैं। हालाँकि उठाए गए प्रश्नों में से एक इकाई के सी. ओ. की क्षमता से संबंधित था, जहाँ अभियुक्तों को बाद में एस. सी. एम. को बुलाने, गठित करने और पूरा करने के लिए कुर्की पर भेजा गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने तथ्यों पर पाया कि एक बड़े आरोप के संबंध में अपराध साबित नहीं हुआ था। हालाँकि यह पाया गया कि एक मामूली अपराध के संबंध में आरोप साबित हो गया और इस प्रकार उनके सेवानिवृत्ति लाभों की रक्षा करने वाले परिणामी निर्देशों के साथ सात दिनों की नजरबंदी की सजा दी गई।

9. राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल अपील सं.6679/2015 में सिविल रिट याचिका सं.401/2014 को खारिज करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, जयपुर के सेवा से बर्खास्तगी और एससीएम द्वारा दिए गए कठोर कारावास की सजा को चुनौती देने/अस्वीकार करने के फैसले की पुष्टि करते हुए इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है। इस मामले में तथ्यों के आधार पर चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि उठाए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न संलग्न इकाई के सी. ओ. की क्षमता से

संबंधित था, ताकि एस. सी. एम. को बुलाया जा सके, गठित किया जा सके और पूरा किया जा सके।

10. इन अपीलों में, इस न्यायालय के दिनांक 12.11.2014 के आदेश द्वारा, मि. अरूण मोहन और सुश्री ज्योति सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इस न्यायालय की सहायता के लिए न्यायालय मित्र नियुक्त किया गया था। हम उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए बहुत आभारी हैं। श्री अरुण मोहन, विद्वान न्यायालय मित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एससीएम के निर्णय से अपील की अनुपस्थिति में दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ भारी होगी, लेकिन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के साथ उस कारक को संशोधित किया जाएगा जो 16.02.2008 से लागू हुआ था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा विचार की गई खंड 120 के तहत ध्यान दें 5 को पहले ही सरकारी आदेश दिनांक 28.01.2001 के माध्यम से हटा दिया गया था। अपनी प्रस्तुति में, उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 20 में दिखाई देने वाली सजा, "कई संभावित अपराधों में से केवल धारा 34,37 और 69 में परिकल्पित अपराधों पर ही एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, जो एस. सी. एम. के असाधारण और असाधारण चरित्र को और मजबूत करता है" सही नहीं था। सुश्री ज्योति सिंह, विद्वान न्यायालय मित्र ने प्रस्तुत किया कि एस. सी. एम. केवल सेना अधिनियम में उपलब्ध है और वायु सेना अधिनियम या नौसेना अधिनियम में नहीं, कि एस. सी. एम. में कानून सम्यक प्रक्रिया का कम पालन किया जाता है, भले ही क़ानून में निहित प्रक्रिया निष्पक्ष मुकदमे की अवधारणा के अनुरूप थी, कि एस. सी. एम. में दी गई सजा की मात्रा अपराधों के लिए बेहद असमान थी और एस. सी. एम. के आयोजन को सक्षम करने वाले प्रावधानों का उपयोग दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। उसकी प्रस्तुति में एक अभियुक्त पर अभियुक्त की मूल इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा चलाया

जाना चाहिए। श्री आर. बालासुब्रमण्यम भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए यह प्रस्तुत करते हुए कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि यह केवल एक इकाई का सी. ओ. है जिससे आरोपी संबंधित है, जो वैध रूप से एक एस. सी. एम. का आयोजन, गठन और पूरा कर सकता है और उसके अनुसार एक इकाई का सी. ओ. भी जिसमें आरोपी को संलग्न किया गया था या बाद में कुर्की पर भेजा गया था, आवश्यक क्षमता होगी, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेखा पल्ली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार का समर्थन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय से उत्पन्न मामलों में, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अधिवक्ता के नेतृत्व में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं था।

11. अधिनियम का अध्याय X "कोर्ट मार्शल" से संबंधित है और संबंधित धाराएँ हैं:-

108. कोर्ट के प्रकार-मार्शल-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चार प्रकार के न्यायालय होंगे-युद्ध, अर्थात -

(क) सामान्य कोर्ट-मार्शल;

(ख) जिला अदालतें-मार्शल;

(ग) सारांश सामान्य कोर्ट-मार्शल; और

(घ) संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल।

109. सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति- केंद्र सरकार या सेना प्रमुख या सेना प्रमुख के वारंट द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त किसी भी अधिकारी द्वारा एक सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाया जा सकता है।

110. जिला कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति।-जिला कोर्ट-मार्शल एक ऐसे अधिकारी

द्वारा बुलाया जा सकता है जिसे सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति है या किसी ऐसे अधिकारी के वारंट द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी भी अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है।

112. एक संक्षिप्त सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति- निम्नलिखित अधिकारियों को एक संक्षिप्त सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति होगी, अर्थात् -(क) केंद्र सरकार या सेना प्रमुख के आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त एक अधिकारी;

(ख) सक्रिय सेवा पर, क्षेत्र में बलों की कमान संभालने वाला अधिकारी, या इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी;

(ग) सक्रिय सेवा पर नियमित सेना के किसी भी अलग हिस्से का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, जब उसकी राय में, अनुशासन और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवहार्य नहीं है कि किसी अपराध का मुकदमा सामान्य कोर्ट-मार्शल द्वारा किया जाना चाहिए।

113. सामान्य कोर्ट-मार्शल की संरचना।- एक सामान्य कोर्ट-मार्शल में कम से कम पाँच अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक ने कम से कम तीन पूरे वर्षों के लिए एक कमीशन आयोजित किया है और जिनमें से कम से कम चार कप्तान से कम रैंक के नहीं हैं।

114. जिला कोर्ट-मार्शल की संरचना-जिला कोर्ट-मार्शल में कम से कम तीन अधिकारी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक ने कम से कम दो पूरे वर्षों के लिए एक आयोग आयोजित किया है।

115. सारांश सामान्य कोर्ट-मार्शल की संरचना-एक संक्षिप्त सामान्य कोर्ट-मार्शल में कम से कम तीन अधिकारी शामिल होंगे।

116. सारांश कोर्ट-मार्शल-(1) एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल किसी भी कोर, विभाग या नियमित सेना की टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित किया जा सकता है, और केवल वही अदालत का गठन करता है।

(2) कार्यवाही में दो अन्य ए व्यक्ति भाग लेंगे जो अधिकारी या कनिष्ठ आयोग अधिकारी होंगे या दोनों में से एक होंगे, और जो इस तरह के नहीं होंगे, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी या पुष्टि की जाएगी।!

118. सामान्य और संक्षिप्त सामान्य अदालतों की शक्तियाँ-मार्शल।-एक सामान्य या संक्षिप्त सामान्य न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति पर दंडनीय किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने और उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा देने की शक्ति होगी।

119. जिला कोर्ट-मार्शल की शक्तियाँ -जिला न्यायालय को एक अधिकारी या एक कनिष्ठ कमीशन अधिकारी के अलावा इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति पर उसमें दंडनीय बनाए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने और दो साल से अधिक की अवधि के लिए मृत्यु, परिवहन या कारावास की सजा के अलावा इस अधिनियम द्वारा अधिकृत कोई भी सजा देने की शक्ति होगीःबशर्ते कि जिला न्यायालय किसी वारंट अधिकारी को कारावास की सजा नहीं देगा।

120. सारांश कोर्ट-मार्शल की शक्तियाँ-

(1) उप-खंड (2) के प्रावधानों के अधीन, एक संक्षिप्त न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चला सकता है।

(2) जब तत्काल कार्रवाई का कोई गंभीर कारण नहीं होता है और अनुशासन को नुकसान पहुँचाए बिना जिला कोर्ट-मार्शल या सक्रिय सेवा पर कथित व्यक्ति के मुकदमे के लिए एक संक्षिप्त सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने के लिए

सशक्त अधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है। अपराधी, एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल रखने वाला अधिकारी इस तरह के संदर्भ के बिना धारा 34,37 और 69 में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध या अदालत रखने वाले अधिकारी के खिलाफ किसी भी अपराध का प्रयास नहीं करेगा।

(3) एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल इस अधिनियम के अधीन और अदालत का संचालन करने वाले अधिकारी की कमान के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है, सिवाय एक अधिकारी, कनिष्ठ कमीशन अधिकारी या वारंट अधिकारी के।

(4) एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल कोई भी सजा पारित कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत पारित की जा सकती है, सिवाय मौत या परिवहन की सजा या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अवधि के लिए कारावास के।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट सीमा एक वर्ष होगी यदि संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल रखने वाला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के पद का है, और तीन महीने यदि ऐसा अधिकारी उस पद से नीचे है।

12. सेना नियम 1954 के अध्याय V की खंड 1 में नियम 22 के उप-नियम 2 और 3 के प्रावधान (जिसे इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) उप-शीर्षक "कमांडिंग ऑफिसर्स की शक्ति" के तहत एससीएम द्वारा परीक्षण से संबंधित मुद्दों से भी निपटते हैं। उक्त नियम 22 निम्नानुसार हैः

“22. प्रभार की सुनवाई।–

(1) अधिनियम के अधीन व्यक्ति के खिलाफ प्रत्येक आरोप की सुनवाई अभियुक्त की उपस्थिति में कमांडिंग अधिकारी द्वारा की

जाएगी।अभियुक्त को अपने विरुद्ध किसी भी गवाह से जिरह करने और ऐसे गवाह को बुलाने और ऐसा बयान देने की पूरी स्वतंत्रता होगी जो उसके बचाव के लिए आवश्यक होः

बशर्ते कि जहां अभियुक्त के खिलाफ आरोप जांच न्यायालय द्वारा जांच के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें उस अभियुक्त के संबंध में नियम 180 के प्रावधानों का उपयोग किया गया है, कमांडिंग अधिकारी उप-नियम (1) में प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

(2) कमांडिंग अधिकारी अपने समक्ष लाए गए आरोप को खारिज कर देगा यदि उसकी राय में साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, और ऐसा तब कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि आरोप के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिएः

बशर्ते कि कमांडिंग अधिकारी धारा की उप-धारा (2) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उस आरोप को खारिज नहीं करेगा, जिस पर उसे प्रतिबंध लगाया गया है। 120 उच्चतर प्राधिकारी के संदर्भ के बिना जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अनुपालन के बाद, यदि कमांडिंग अधिकारी की राय है कि आरोप के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो वह एक उचित समय के भीतर -

(क) खंड 80 के तहत मामले का निपटान परिशिष्ट 3 में दिए गए तरीके और प्रपत्र के अनुसार किया जाए; या

(ख) मामले को उचित वरिष्ठ सैन्य प्राधिकरण के पास भेजें; या

(ग) साक्ष्य को लेखन तक सीमित करने के उद्देश्य से मामले को स्थगित करें; या

(घ) यदि अभियुक्त वारंट अधिकारी के पद से नीचे है, तो संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके मुकदमे का आदेश दें:

बशर्ते कि कमांडिंग अधिकारी कथित अपराधी के मुकदमे के लिए जिला कोर्ट-मार्शल या सक्रिय सेवा पर अतिरिक्त सामान्य कोर्ट-मार्शल बुलाने के लिए सशक्त अधिकारी के संदर्भ के बिना संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमे का आदेश नहीं देगा, जब तक कि -

(क) अपराध वह है जिस पर वह उस अधिकारी के किसी भी संदर्भ के बिना संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चला सकता है; या

(ख) उनका मानना है कि तत्काल कार्रवाई करने का गंभीर कारण है और अनुशासन को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

(4) जहां इस नियम के उप-नियम (3) के अनुसार लिया गया साक्ष्य उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का खुलासा करता है जो जांच का विषय था, वहां कमांडिंग अधिकारी इस प्रकार लिए गए साक्ष्य के साथ-साथ मूल आरोप की जांच के आधार पर उपयुक्त आरोप (आरोप) बना सकता है।"

13. "सामान्य और जिला न्यायालय मार्शल" शीर्षक के तहत नियमों की खंड 2 में और "न्यायालय का आयोजन" उप-शीर्षक के तहत, नियमों के नियम 39 और 40 निम्नानुसार हैं:

"39, कोर्ट-मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और अयोग्यता।–

(1) एक अधिकारी कोर्ट-मार्शल पर सेवा करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह अधिनियम के अधीन नहीं है।

(2) एक अधिकारी को सामान्य या जिला कोर्ट-मार्शल पर सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि वह -

(क) एक अधिकारी है जिसने न्यायालय को बुलाया है; या

(ख) अभियोजक या अभियोजन पक्ष का गवाह है; या

(ग) मुकदमे से पहले आरोपों की जांच की, या साक्ष्य के सारांश को हटा दिया, या उन मामलों के संबंध में जांच अदालत का सदस्य था जिन पर आरोपी के खिलाफ आरोप स्थापित किए गए हैं, या स्क्वाड्रन, बैटरी, कंपनी या अन्य कमांडर था, जिसने मामले की प्रारंभिक जांच की, या पिछले कोर्ट-मार्शल का सदस्य था जिसने उसी अपराध के संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया था; या

(घ) अभियुक्त का या उस दल का कमांडिंग अधिकारी है जिससे अभियुक्त संबंधित है; या

(ई) मामले में व्यक्तिगत हित है।

(3) प्रोवोस्ट-मार्शल या सहायक प्रोवोस्ट-मार्शल को सामान्य कोर्ट-मार्शल या जिला कोर्ट-मार्शल में सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

40. जनरल कोर्ट-मार्शल की संरचना।–

(1) जहाँ तक संयोजक अधिकारी को व्यवहार्य लगे, विभिन्न कोर या विभागों के अधिकारियों के लिए एक सामान्य कोर्ट-मार्शल की रचना की जाएगी, और किसी भी

मामले में उस कोर या विभाग के अधिकारियों को छोड़कर नहीं, जिससे आरोपी संबंधित है।

(2) एक अधिकारी के मुकदमे के लिए कोर्ट-मार्शल के सदस्य अधिकारी से कम रैंक के नहीं होंगे, जब तक कि संयोजक अधिकारी की राय में, ऐसे रैंक के अधिकारी (लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए) उपलब्ध नहीं हैं।इस तरह की राय को संयोजक आदेश में दर्ज किया जाएगा।

(3) किसी भी मामले में कप्तान के पद से नीचे का अधिकारी फील्ड अधिकारी के मुकदमे के लिए कोर्ट-मार्शल का सदस्य नहीं होगा।"

14. नियमों की खंड 3 में, नियम 109 अदालत और दुभाषिया की शपथ या पुष्टि के साथ संबंधित है जो नियम शपथ और पुष्टि के संबंधित रूपों को भी निर्धारित करता है।एस. सी. एम. की कार्यवाही की समीक्षा से संबंधित नियम 133 निम्नानुसार हैः-

> "133. कार्यवाही की समीक्षा– एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही, घोषणा के तुरंत बाद, खंड 162 के अनुसरण में उनसे निपटने के लिए अधिकृत अधिकारी को (उस कमान के उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता के माध्यम से जिसमें मुकदमा आयोजित किया जाता है) भेजा जाएगा। उसके द्वारा समीक्षा के बाद, उन्हें नियम 146 के उप-नियम (2) के अनुसार संरक्षण के लिए आरोपी व्यक्ति के दल को वापस कर दिया जाएगा।"

15. सभी प्रकार के कोर्ट मार्शल पर लागू "सामान्य प्रावधानों" से संबंधित नियमों की खंड 4 में, नियमों के नियम 146 में निम्नानुसार कहा गया हैः-

"146. कार्यवाहियों का संरक्षण।–

(1) कोर्ट-मार्शल (संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के अलावा) की कार्यवाही, घोषणा के बाद, परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, न्यायाधीश-महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजी जाएगी, और वहां सामान्य कोर्ट-मार्शल के मामले में, सात साल से कम के लिए और किसी अन्य कोर्ट-मार्शल के मामले में, तीन साल से कम के लिए संरक्षित नहीं की जाएगी।

(2) समरी कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही को उस कोर या विभाग के रिकॉर्ड के साथ कम से कम तीन साल के लिए संरक्षित किया जाएगा, जिससे आरोपी संबंधित थे।"

16, अंत में, हम डी. एस. आर. के विनियम 9 और 381 को भी उद्धृत कर सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः-

"9.कमांडिंग ऑफिसर।- इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का कमांडिंग ऑफिसर या तो हैः-

(क) वह अधिकारी जिसे उच्च प्राधिकारी द्वारा कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि वह अपनी शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में समर्थ है, या

(ख) जहां कोई नियुक्ति नहीं की गई है, वह अधिकारी जो तत्काल कमान में है -

(i) वह इकाई जिससे वह व्यक्ति संबंधित है या जुड़ा हुआ है, या

(ii) किसी इकाई का कोई अलग टुकड़ी या एक विशिष्ट बड़ा अलग हिस्सा जिसके साथ व्यक्ति कुछ समय के लिए सेवा कर रहा है।

और जिसके संबंध में इन विनियमों के तहत या सेवा की प्रथा के अनुसार ऐसे अधिकारी का कर्तव्य है कि वह एक कमांडिंग अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करे।"

381- रेगिस्तानियों का मुकदमा-सामान्य परिस्थितियों में रेगिस्तान के लिए संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा रेगिस्तान की इकाई के सीओ द्वारा आयोजित किया जाएगा।हालांकि, जब नीचे दी गई तालिका में से एक कॉलम में दिखाई गई इकाई से कोई पलायन करने वाला या अनुपस्थित व्यक्ति कॉलम दो में विपरीत दिखाई गई इकाई के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, या उसके द्वारा ले लिया जाता है, और बाद की इकाई के बल पर ठीक से संलग्न किया जाता है और लिया जाता है, तो वह, प्रदान किए गए साक्ष्य, विशेष रूप से पहचान का प्रमाण, मोटी इकाई के साथ उपलब्ध है, सारांश कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

उस इकाई के ओसी द्वारा जब कॉलम एक में दिखाई गई इकाई उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र या विदेशों में सेवा कर रही है या विद्रोह विरोधी अभियान या सक्रिय शत्रुता या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगी हुई है।

किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति पर उस इकाई के सी. ओ. के अलावा एक सी. ओ. द्वारा आयोजित संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिसमें वह व्यक्ति ठीक से एक इकाई से संबंधित है, जिससे वह व्यक्ति जुड़ा हो सकता है।

उसके द्वारा अपराध किए जाने के बाद भी एक इकाई जिससे व्यक्ति की संपत्ति संबंधित है।

तालिका

स्तम्भ एक	स्तम्भ दो

बख्तरबंद कोर रेजिमेंट	सशस्त्र कोर केंद्र और स्कूल
तोपखाने की एक इकाई	रेजीमेंटल सेंटर की स्थापना
इंजीनियरों की एक इकाई का गठन किया	मुख्यालय इंजीनियर समूह,
यूनिट ऑफ सिग्नल्स	सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर
इन्फैन्ट्री बटालियन	रेजीमेंटल सेंटर संबंधित
गोरखा राइफल बटालियन का गठन	गोरखा रेजिमेंटल सेंटर
ए. एस. सी. इकाई.	ए. एस. सी. केंद्र संबंधित
आर. वी. फसलें.	आर. वी. सी. केंद्र

इस नियम का उद्देश्य किसी भी संयोजक अधिकारी की शक्ति को सीमित करना नहीं है, जो अपने विवेक से किसी भी स्थान पर जनरल, समरी जनरल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमे का आदेश दे सकता है, यदि ऐसा कोई पाठ्यक्रम अनुशासन के हित में वांछनीय प्रतीत होता है।"

17. अधिनियम के अध्याय X में चार प्रकार के कोर्ट मार्शल की स्थापना के बाद, ऐसे न्यायालयों-मार्शल, ऐसे कोर्ट मार्शल की संरचना और ऐसे कोर्ट मार्शल की शक्तियों को बुलाने के लिए किसे सशक्त किया गया है, जैसे मुद्दों से संबंधित है। खंड 118 के अनुसार, जी. सी. एम. को अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति पर दंडनीय किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने और पारित करने की शक्ति है। अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई सजा खंड 112 के पढ़ने से पता चलता है कि सक्रिय सेवा में रहते हुए एक एस. जी. सी. एम. बुलाया जा सकता है यदि अनुशासन और सेवा की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर संतोष किया जाता है कि जी. सी. एम. द्वारा अपराध का मुकदमा चलाना व्यावहारिक नहीं होगा। खंड 118 के अनुसार, ऐसे एस. जी. सी. एम. को फिर से अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति पर किसी भी दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने और उसके द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित करने का अधिकार है। अधिनियम की खंड 119 में कहा गया है कि एक अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक डी. सी. एम. को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन खंड 119 सजा की शक्ति को सीमित करती है, जिसमें एक डी. सी. एम. दो साल से अधिक की अवधि के लिए मौत, परिवहन या कारावास की सजा नहीं दे सकता है। इसके अलावा, एक डीसीएम एक वारंट अधिकारी को कारावास की सजा नहीं दे सकता है। धारा 109,112 और 119 संबंधित धाराओं में उल्लिखित अधिकारियों को क्रमशः ऐसे जी. सी. एम., एस. जी. सी. एम. और डी. सी. एम. बुलाने की शक्ति प्रदान करती हैं।जी. सी. एम., एस. जी. सी. एम. और डी. सी. एम. की संरचना को फिर से क्रमशः धारा 113,115 और 114 में निर्धारित किया गया है।

18, एस. सी. एम. के संबंध में, खंड 120 में कहा गया है कि एक एस. सी. एम. अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चला सकता है, लेकिन उप-खंड (4) और (5) सजा के पुरस्कार को सीमित करती है। उप-धारा (4) के अनुसार, एक एस. सी. एम. किसी भी सजा को पारित कर सकता है जो अधिनियम के तहत निर्धारित की जा सकती है, सिवाय मौत या परिवहन या कारावास की सजा के। उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सीमा। खंड 120 की उप-खंड (5), तब एक वर्ष के स्तर तक की सीमा निर्धारित करती है, यदि एस. सी. एम. धारण करने वाला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद का है और उससे ऊपर का है और तीन महीने के स्तर पर यदि एस. सी. एम. धारण करने वाला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से नीचे है।

19. अधिनियम की खंड 116 किसी भी कोर, विभाग और नियमित सेना की टुकड़ी के सी.ओ. को एस.सी.एम. आयोजित करने का अधिकार देती है और विशेष रूप से कहती है कि वह अकेले ही न्यायालय का गठन करेगा।उप-धारा (2) तब यह विहित करती है कि कार्यवाही में, तथापि, उसमें विनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह से भाग लिया जाएगा। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों को शपथ या पुष्टि नहीं दी जानी चाहिए।खंड 113,115 और 114 के विपरीत, जहां संबंधित न्यायालय-मार्शल की संरचना में कम से कम तीन अधिकारी शामिल होने के लिए निर्धारित किया गया है, यह अकेले सी. ओ. है जो एस. सी. एम. के संबंध में खंड 116 के तहत न्यायालय का गठन करता है। इसके अलावा, नियमों के नियम 39 और 40 के तहत, आरोपी या उस कोर के सी. ओ. को विशेष रूप से जी. सी. एम. या डी. सी. एम. पर सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है और जी. सी. एम. की संरचना में विभिन्न कोर या विभागों के अधिकारी शामिल होने चाहिए। हालाँकि ऐसा कोई प्रतिबंध एस. सी. एम. पर लागू नहीं होता है और वास्तव में सी. ओ. को स्वयं न्यायालय का गठन करना चाहिए। इस प्रकार अधिनियम ने एक एकल व्यक्ति, अर्थात् सी. ओ. को कठोर शक्ति दी है, जिसे अकेले न्यायालय का गठन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शक्ति प्रतिबंधों के साथ आती है जहां तक खंड 120 की उप-खंड (4) और (5) के संदर्भ में सजा देने की शक्ति का संबंध है।हालाँकि इस तरह के प्रतिबंधों के बावजूद शक्ति काफी कठोर है। इस तरह की शक्ति प्रदान आदेशने का कारण स्पष्ट है कि सैनिकों और इकाइयों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए, सी. ओ. के पास कुछ विशेष शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि यह वह अनुशासन है जो काफी हद तक इकाई को बांधता है और इसे एक सह-एकजुट बल बनाता है।

20. इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करने में आत्यन्तिक रूप से सही था कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए और जब

यह बिल्कुल जरूरी हो तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। उस ओर से संतुष्टि या तो लिखित रूप में व्यक्त की जानी चाहिए या रिकॉर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए, विशेष रूप से जब सशस्त्र बल न्यायालय अधिनियम, 2007 के लागू होने के साथ किसी न्यायालय द्वारा मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

21. अब हम इस सवाल से निपटते हैं कि एससीएम द्वारा किस तरह के अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। एस. सी. एम. खंड 120 की उप-खंड (1) के आधार पर अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चला सकता है, लेकिन यह सामान्य सिद्धांत खंड 120 की उप-खंड (2) में दिखाई देने वाले प्रावधानों के अधीन है।खंड 120 की उप-खंड (2) कुछ अपराधों से संबंधित है जिनके संबंध में कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं।इस प्रकार निर्धारित अपराध वे हैं जो अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के तहत या न्यायालय का संचालन करने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडनीय हैं।अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के अलावा, कई अन्य प्रावधान हैं जहां विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन किया जाता है और उनसे निपटा जाता है।उदाहरण के लिए अधिनियम के अध्याय VI में, खंड 38 त्याग के अपराध से संबंधित है, खंड 39 छुट्टी बिना अनुपस्थिति के अपराध से संबंधित है, खंड 40 एक वरिष्ठ अधिकारी को मारने या धमकी देने से संबंधित है, खंड 41 वरिष्ठ अधिकारी की अवज्ञा से संबंधित है, खंड 42 अवज्ञा आदि से संबंधित है। ऐसे कई अपराधों में से केवल धारा 34,37 और 69 का उल्लेख उप-धारा (2) में किया गया है, जिसके संबंध में प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। उप-धारा (2) लागू होती है। इसके अतिरिक्त, एक और श्रेणी, अर्थात् "न्यायालय धारण करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई भी अपराध" भी निर्दिष्ट की गई है।न्यायालय धारण करने वाले अधिकारी के खिलाफ जिन अपराधों का निर्देश दिया जाता है, उनमें मामले के तथ्यों के आधार पर धारा 40,41,42 आदि के तहत

अपराध शामिल हो सकते हैं।

22. खंड 120 की उप-खंड (2) में निर्धारित किया गया है कि ऐसे निर्धारित अपराधों के संबंध में, सामान्य परिस्थितियों में, एक एस. सी. एम. उस अधिकारी को संदर्भित किए बिना अभियुक्त पर मुकदमा नहीं चलाएगा जो अन्यथा नियमित पाठ्यक्रम में एक डी. सी. एम. या सक्रिय सेवा में रहते हुए एक एस. जी. सी. एम. को बुलाने के लिए सशक्त है।इसमें आगे कहा गया है कि यदि तत्काल कार्रवाई का कोई गंभीर कारण नहीं है, तो संबंधित अधिकारी को इस तरह का संदर्भ दिया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर इस तरह से निर्धारित किसी भी अपराध के संबंध में इस तरह के संदर्भ के बिना मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, यानी अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के तहत या अधिनियम की धारा 34,37 और 69 रखने वाले अधिकारी के खिलाफ, अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के अलावा अन्य मामलों में या न्यायालय धारण करने वाले अधिकारी के खिलाफ अपराधों में ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इस प्रकार यह प्रावधान अपराधों को दो खंडों में वर्गीकृत करता है अर्थात वे जिन्हें संदर्भ की आवश्यकता होती है और जो नहीं करते हैं।यह अंतर नियम 22 के उप नियम 2 से भी ध्यान देने योग्य है जो यह आदेश देता है कि सी. ओ. उन अपराधों के संबंध में किसी आरोप को खारिज नहीं करेगा जिनके लिए अधिनियम की खंड 120 (2) के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें इस दलील को प्रतिग्रहण करना करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ सं.20 में इस आशय की सजा दी गई है कि केवल अधिनियम की खंड 34,37 और 69 के तहत अपराधों का मुकदमा एससीएम द्वारा चलाया जा सकता है, यह सही नहीं है।

23. खंड 120 (2) में उपरोक्त प्रावधान में वरिष्ठ प्राधिकारी के संदर्भ की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में सोचा जाता है कि यह नियम के नियम 22 (3) के

प्रावधान में फिर से प्रतिध्वनित होता है, एक लाभकारी प्रावधान है और एक सी. ओ. को प्रदान की गई कठोर शक्ति के प्रयोग पर रोक है और इसका सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।इस आवश्यकता के गैर-पालन के लिए एक मामला रिकॉर्ड पर बनाया जाना चाहिए और किसी भी विचलन या वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-पालन को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 34,37 और 69 के तहत अपराध विशेष श्रेणियां या प्रकार के अपराध हैं जहां एक डी. सी. एम. या एस. जी. सी. एम. को बुलाने के लिए सशक्त अधिकारी का संदर्भ अनिवार्य माना जाता है जब तक कि तत्काल कार्रवाई के लिए गंभीर कारण न हों। इसी तरह, न्यायालय धारण करने वाले अधिकारी के खिलाफ अपराध, जहां वह अधिकारी संभवतः "अपने मामले में न्यायाधीश हो सकता है", को भी उसी स्तर पर रखा जाता है और उप-धारा (2) के तहत इसी तरह का संदर्भ दिया जाना चाहिए।इस तरह के संदर्भ की मांग करने में शक्ति का प्रयोग और इसके संबंध में परिणामी विचार इन अपराधों के संबंध में जुड़ी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

24. अब हम मूल प्रश्न की ओर मुड़ते हैं कि कौन सा सी. ओ. एस. सी. एम. को बुलाने, गठित करने और पूरा करने में सक्षम है। क्या यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे आरोपी संबंधित था।या उस इकाई का सी. ओ. जिससे वह जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ था।इस संबंध में संभवतः तीन प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं।

ए) एक अभियुक्त जो अपनी नियमित इकाई का हिस्सा रहते हुए एक अपराध का गठन करने वाला कार्य करता है, उस पर एस. सी. एम. द्वारा उसके अपने सी. ओ. यानी इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।

बी) एक अभियुक्त एक अलग इकाई से संलग्नक होने के दौरान एक अपराध का गठन करने वाला कार्य करता है और इसलिए उस पर ऐसी इकाई

के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जिस पर उसे संलग्नक पर भेजा गया था।ऐसे मामलों में अपराध तब किया जाएगा जब आरोपी कुर्की पर था।

ग.) अपनी नियमित इकाई का हिस्सा रहते हुए अपराध का गठन करने वाला कार्य करने वाले अभियुक्त को बाद में एक अलग इकाई में कुर्की पर भेजा जाता है और फिर ऐसी इकाई के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।, इकाई जहाँ अपराध के बाद उसे कुर्की पर भेजा गया था।

25. नियम 39 के विपरीत, जो विशेष रूप से अभियुक्त के सी. ओ. या उस कोर के सी. ओ. को अयोग्य ठहराता है जिससे अभियुक्त जी. सी. एम. या डी. सी. एम. पर सेवा करने से संबंधित है, उस इकाई के सी. ओ. पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे अभियुक्त एस. सी. एम. द्वारा अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय से संबंधित है। ऊपर वर्णित अपराधों की उपरोक्त तीन श्रेणियों में से पहला इसलिए निश्चित रूप से उस इकाई के सी. ओ. द्वारा परीक्षण किया जा सकता है जिससे वह संबंधित है।यदि अपराध का गठन करने वाला कार्य उस इकाई से जुड़ा हुआ है जब ऐसा कार्य किया गया था, तो दूसरी श्रेणी में आने वाले मामलों के संबंध में, अपराध का तार्किक रूप से उस इकाई के सी. ओ. द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिससे आरोपी जुड़ा हुआ था। क्या अभियुक्त तब इस बात पर जोर दे सकता है कि केवल उसकी मूल इकाई के सी. ओ. को ही एस. सी. एम. द्वारा उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्या यह कहा जा सकता है कि मूल इकाई के साथ उसके पूर्व संबंध को इस हद तक शासी कारक के रूप में लिया जाना चाहिए कि इकाई का सामान्य संबंध और विचाराधीन अपराध विस्थापित हो जाए। हमारा जवाब है नहीं यदि खंड 120 (2) की आवश्यकताओं का अन्यथा अनुपालन और संतुष्टि की जाती है, तो ऐसी संलग्न

इकाई का सी. ओ. बुलाने, गठन करने और पूरा करने में सक्षम है।

एससीएम। यह उनकी इकाई में है कि विचाराधीन अपराध किया गया था और उस अर्थ में वह मामले की निगरानी में होगा।मूल इकाई के सी. ओ. का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं होगा।

26. तीसरी श्रेणी हालांकि कुछ चिंता पैदा करती है।इसके तहत दो उप श्रेणियां हो सकती हैं।पहले में, अपराध के बारे में ही पता चल सकता है, हालांकि अपराध मूल इकाई में किया गया था, जब आरोपी को कुर्की पर भेजा गया था।दूसरा, जो विचाराधीन मामलों में अपनाया गया सामान्य तरीका है, एक आरोपी को केवल उस अन्य इकाई के सी. ओ. द्वारा एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाने के लिए दूसरी इकाई में कुर्की पर भेजा जा सकता है। पूर्ववर्ती इकाई के साथ संबंधित होने और उस इकाई के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण एक अपराध का गठन करने वाले अधिनियम का आयोग, जहां उसे बाद में कुर्की पर भेजा जाता है, आम तौर पर विचाराधीन इकाइयों में से पूर्व उपयुक्त होगा।लेकिन इस मामले पर विचार करने और विशुद्ध रूप से पूर्व या पूर्व इकाई के साथ इस तरह के संबंध या सांठगांठ के दृष्टिकोण से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

27. किसी मामले में, अपराध स्वयं पूर्व इकाई के सी. ओ. के खिलाफ किया गया हो सकता है या सी. ओ. मुद्दे के मामलों पर प्रतिबिंबित करने वाला एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है या अनुशासन के उद्देश्यों के लिए अभियुक्त को विचाराधीन इकाई से बाहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में विचाराधीन इकाई में एस. सी. एम. के संचालन के दौरान भी अभियुक्त की उपस्थिति अनुशासन बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकती है।स्थितियाँ डिग्री या संदर्भ में भिन्न हो सकती हैं और औचित्य और समीचीनता की अवधारणा की मांग हो सकती है

कि अभियुक्त को संलग्नक पर भेजा जाए और एक अलग इकाई में मुकदमा चलाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का अनुच्छेद 24 उस ओर से अपनी चिंता और इस तथ्य को दर्शाता है कि उच्च न्यायालय ऐसी जटिलताओं के लिए जीवित था।लेकिन इस विचार पर कि जिस इकाई से आरोपी संबंधित है, उसके सी. ओ. अक्षम होंगे, उच्च न्यायालय को अभियुक्त की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण को प्रतिग्रहण करना करने के लिए राजी किया गया।

28. हम इस स्तर पर डी. एस. आर. के विनियम 9 का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।इस विनियमन के तहत सी. ओ. या तो हो सकता हैः-

क) जिसे उच्च प्राधिकारी द्वारा किसी निगम में निहित शक्तियों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए निगम अधिकारी नियुक्त किया गया है; या

ख) वह व्यक्ति जो उस इकाई की तत्काल कमान संभालता है जिससे वह व्यक्ति संबंधित है; या

ग) वह व्यक्ति जो उस इकाई की तत्काल कमान संभालता है जिससे वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है; या

घ) वह व्यक्ति जो किसी इकाई के किसी भी टुकड़ी या विशिष्ट आकार के अलग हिस्से की तत्काल कमान संभालता है, जिसके साथ वह व्यक्ति कुछ समय के लिए सेवा कर रहा है।

29. विनियमन 9 अपनी चौड़ाई और आयाम के साथ संभवतः किसी भी स्थिति को शामिल कर सकता है ताकि कोई विलाप व्यक्त करने की गुंजाइश न रहे जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 24 में किया गया था।यदि प्रक्रिया में निष्पक्षता की अवधारणा की मांग की जाती है, जैसा कि नियमों के नियम 39 के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जिस इकाई से कोई आरोपी संबंधित है, उसके सी. ओ. को जी. सी.

एम. या डी. सी. एम. पर सेवा करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, तो अपराध के संबंध में ऐसे सी. ओ. की स्थिति और भूमिका की परवाह किए बिना, उस इकाई के सी. ओ. पर एस. सी. एम. बुलाने का हकदार एकमात्र प्राधिकरण होने का आग्रह करना पूरी तरह से विरोधाभास होगा। धारा 116 और '120 इस तरह के किसी भी निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके विपरीत किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में में, विनियमन 9 निश्चित रूप से मार्गदर्शक कारक हो सकता है।खंड 116 में "कमांडिंग ऑफिसर" अभिव्यक्ति किसी भी स्पष्टीकरण से योग्य नहीं है कि वह उस इकाई का सी. ओ. होना चाहिए जिससे आरोपी संबंधित है।विनियमन 9, हमारे विचार में, इस तरह की व्याख्या प्रदान करता है और निष्पक्षता और निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।

30. रेग्युलेशन 381, रेगिस्तानियों के परीक्षण के संदर्भ में एक विशेष प्रावधान है। यदि अभियुक्त जिस इकाई से संबंधित है, वह उच्च दृष्टिकोण वाले क्षेत्रों या विदेशों में सेवा कर रही है या विद्रोह विरोधी अभियानों या सक्रिय शत्रुता में लगी हुई है, तो अभियुक्त पर उसमें निर्दिष्ट इकाइयों के सी. ओ. द्वारा निर्धारित तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन विनियमन 381 एकमात्र अपवाद नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है और यह निष्कर्ष कि सभी परिस्थितियों में, विनियमन 381 द्वारा निपटाए गए मामलों के अलावा, यह उस इकाई का सी. ओ. है जिससे केवल आरोपी संबंधित है जो एस. सी. एम. बुलाने, गठित करने और पूरा करने के लिए सक्षम है, गलत है।

31. यह ध्यान देने योग्य है कि जिस अभिव्यक्ति से अभियुक्त संबंधित है, उसका उल्लेख नियमों के नियम 39 में मिलता है जैसा कि ऊपर जीसीएम या डीसीएम के संदर्भ में किया गया है, लेकिन एससीएम के संबंध में नहीं। नियमों के नियम 133 के तहत एक एस. सी. एम. की कार्यवाही को घोषणा के तुरंत बाद उस कमान के उप

न्यायाधीश महाधिवक्ता द्वारा से अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमें मुकदमा आयोजित किया जाता है। दूसरी ओर, नियमों के नियम 146 के तहत एक एस. सी. एम. की कार्यवाही को उस दल या विभाग के रिकॉर्ड के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए जिससे आरोपी संबंधित थे। इस प्रकार यह संभव और सुविचारित है कि एस. सी. एम. द्वारा मुकदमा उस इकाई के अलावा किसी अन्य इकाई में आयोजित किया जा सकता है जिससे आरोपी संबंधित है।नियम 39 और 146 आगे खुलासा करते हैं कि जहां भी अधिनियम उस इकाई या विभाग को निर्दिष्ट करना चाहता था "जिससे आरोपी संबंधित था" उसने इसे बहुत स्पष्टता के साथ किया है। सी. ओ. के संबंध में ऐसी कोई योग्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है जिसे एस. सी. एम. का आयोजन, गठन और पूरा करना है।

32. अंत में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नियमावली में खंड 120 के नीचे दिए गए ध्यान दें 5 से संभवतः यह संकेत मिल सकता है कि किसी एन. सी. ओ. या सिपाही को डी. एस. आर. के विनियमन 381 में दिए गए प्रावधान के अलावा एस. सी. एम. द्वारा परीक्षण के लिए किसी अन्य इकाई से जोड़ा नहीं जा सकता है। संसद द्वारा अधिनियमित किसी अधिनियम की खंड के तहत ऐसे ध्यान दें की प्रभावकारिता और बल के सवाल में गए बिना, वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह ध्यान देना पर्याप्त है कि इस ध्यान दें को 28.08.2001 से हटा दिया गया था।

33. परिसर में, हमारा मानना है कि यह जरूरी नहीं है कि एस. सी. एम. को उस इकाई के सी. ओ. द्वारा बुलाया जाए, गठित किया जाए और पूरा किया जाए जिसमें आरोपी शामिल थे।जिस इकाई से अभियुक्त को संबद्ध किया गया था या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए कुर्की पर भेजा गया था, उस इकाई के सी. ओ. के लिए यह सक्षम और अनुज्ञेय है कि वह ऐसे अभियुक्त पर कानून द्वारा ज्ञात तरीके से एस. सी. एम. बुलाकर, गठित करके और पूरा करके, यानी अधिनियम की धारा 116 और

120 और अन्य सांविधिक प्रावधानों की सीमा के भीतर, मुकदमा चलाए। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार का पूरी तरह से समर्थन और पुष्टि करते हैं कि एससीएम एक अपवाद है और यह अनिवार्य है कि कार्रवाई की तत्कालता के लिए एक मामला बनाया जाना चाहिए।एस. सी. एम. बुलाने के कारणों का अच्छी तरह से स्पष्ट कारणों से पालन किया जाना चाहिए या रिकॉर्ड को स्वयं इस तरह के उपाय को उचित ठहराना चाहिए।

34. अलग होने से पहले, हमें शिकायतों के निवारण से संबंधित संस्थागत तंत्र को मजबूत करने सहित सेवा और पेंशन मामलों की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों का उल्लेख करना चाहिए, जो सिफारिशें 2015 की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के पृष्ठ 172 पर निम्नलिखित रूप में दिखाई देती हैं।

शर्तेंः-

> "समिति ने सिफारिश की है कि पर्यावरण को संवेदनशील बनाया जा सकता है कि एस. सी. एम. के प्रावधान का उपयोग संयम और असाधारण रूप से और अधिमानतः केवल उन परिचालन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां नियमित परीक्षण का सहारा लेना व्यावहारिक नहीं है या जब संक्षिप्त/प्रशासनिक हो।
>
> कार्रवाई अनुशासन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि एस. सी. एम. एक अपवाद है न कि नियम और यह मूल रूप से शांति-काल के प्रावधान या नियमित उपाय के लिए भी नहीं था। आने वाले समय में, अधिनियम पुस्तिका में इस तरह के प्रावधान की वांछनीयता की जांच न्यायसंगतता और

संवैधानिक मानदंडों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली अधिक मजबूत प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापन की उपयुक्तता के साथ की जा सकती है। हालाँकि हम सावधान कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह से वर्दीधारी सेवाओं में अनुशासन की आवश्यकता को कम नहीं आंक रहे हैं, बल्कि केवल यह कह रहे हैं कि जब अनुशासन को लागू करने के अन्य प्रभावी उपकरण उपलब्ध हों तो एससीएम को एक नियमित उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

ये सिफारिशें उस दृष्टिकोण का सारांश देती हैं जिसे काफी अच्छी तरह से अपनाने की आवश्यकता है।

35. चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस बिंदु के संबंध में विचार को दरकिनार करते हुए और भारत संघ द्वारा सिविल अपील सं.8360/2010 8830-8835/ 2010 और 8838/2010 अपीलों को अनुमति देते हुए, उसके समक्ष मामलों के गुण-दोष में गए बिना, अभियुक्त के अलावा किसी इकाई के सी ओ की क्षमता के संक्षिप्त आधार पर रिट याचिकाओं की अनुमति दी थी, इसलिए हम मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। संबंधित रिट याचिकाएं गुण-दोष पर विचार के लिए उच्च न्यायालय की फाइल पर बहाल की गई हैं।

36. राजस्थान उच्च न्यायालय से आने वाले मामले, अर्थात् सिविल अपील सं.2547-2550/2011 और सिविल अपील सं.6679/2015 एक अलग आधार पर हैं। इन अपीलों में गुण-दोष पर चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उठाए गए मुद्दों में से एक मुद्दा एस. सी. एम. का गठन करने और उसे पूरा करने के लिए एक अन्य इकाई के सी. ओ. की क्षमता के बारे में था, जिसमें अभियुक्त शामिल था। उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब

चुनौती योग्यता के आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी। इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और इन अपीलों को खारिज करते हैं।

37. इसी तरह, सिविल अपील सी. ए. डी. सं 13803 और 18038/2015 जहां प्रमुख अपराधों को तथ्यों पर साबित नहीं किया गया था, वे भी खारिज किए जाने के योग्य हैं। सी. ओ. की क्षमता से संबंधित मुद्दे का उत्तर यहाँ ऊपर दिए जाने के साथ, मामलों में कुछ भी नहीं बचा है और इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

38. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।